हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 13 अंक : 65 | देहरादून, बुधवार, 28 अगस्त, 2024 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 8

उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली नियुक्ति, सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र 3

खाद्य सुरक्षा के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव ने तलब की रिपोर्ट

देहरादून में गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब के मामलों का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी/एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के ससमय अनुपालन ना होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 68 के तहत न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब से निस्तारण के फलस्वरूप बढ़ती वादों की संख्या तथा इस कारण प्रवर्तन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मण्डल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को आरम्भ करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। इस गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध में 23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आरम्भ में इस लैब की क्षमता 5000 सैम्पलिंग टेस्ट की होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रूद्रपुर में अल्ट्रा मॉर्डन माइक्रोबाइलोजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिक उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन हेतु भी संविदा के आधार पर

- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में दायर वादों की त्वरित सुनवाई हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश
- सीएस राधा रतूड़ी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यों हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से अनुरोध

- त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश
- भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षण
- राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त

8 पदों की स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिव राज्य में अधिकाधिक टेस्टिंग बढ़ाये जाने तथा टेस्टिंग रिपोर्ट समयबद्धता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफ्टी के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल मेनेजमेंट के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को फूड सेफ्टी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने आमजन के लिए सैम्पल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यों को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने ईट राइट इण्डिया अभियान के तहत ईट राइट कैम्पस/ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैम्पस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।

बैठक में जानकारी दी गई कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाये -जाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गयी है। 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये गये। 190 विधिक तथा 519 सर्विलांस नमूने जॉच हेतु लिये गये है। 20 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं तथा न्यायालय द्वारा 09 खाद्य कारोबारियों पर 3,30,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाईल खाद्य विश्लेषण शाला के माध्यम से

आम जनमानस एवं खाद्य कारोबार कर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री की मौके पर जाँच/प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 601 खाद्य पदार्थों की मौके पर सर्वेलांस जाँच की गयी, जिसमें से 529 खाद्य पदार्थ जाँच में सही पाये गये तथा 72 मानकों के अनुरूप नही पाये गये। उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतु 02 नवीन संचल खाद्य विश्लेषणाशालाओं के संचालन हेतु टैक्निकल स्टाफ की आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के अधीन कार्यरत खाद्य संरक्षा तथा-सतर्कता सह अभिसूचना इकाई के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा खाद्य संरक्षा तथा सर्तकता सह अभिसूचना के अधिकारियों की टीम गठित करते हुए चारधाम यात्रा/पर्यटक सीजन में सघन-प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की प्रभावी पैरवी ए०पी०ओ० के माध्यम से कराये जाने हेतु जनपदीय अभिहित अधिकारियों को प्रकरण जिला स्तरीय सलाहकार समिति के समक्ष रखने हुये निर्देशित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दायर विभिन्न वादों का निस्तारण करने वाले न्याय निर्णायक अधिकारी/ए०डी०एम० को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनमानस द्वारा विभागीय हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों/जानकारी की पंजीकरण प्रक्रिया का ऑटो डिजीटाइजेशन कर हेल्पलाईन न0 18001804246 को 24×7 संचालित किये जाने एवं आई०ई०सी० के माध्यम से टोल फ्री न० के व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

उद्योग जगत से सहयोग लेते हुए सी०एस०आर० फंड के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर 1200 स्ट्रीट वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में नेस्ले इण्डिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरम्भ किया गया है तथा जनपद रूद्रप्रयाग, पौडी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड : 11 जिलों में मास्टर प्लान से डेवलप होंगे 23 शहर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 218 अगस्त : इस मास्टर प्लान से उत्तराखंड के 23 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।केंद्र सरकार ने अमृत योजना-2 के तहत उत्तराखंड के 23 शहरों के GIS आधारित मास्टर प्लान के लिए तीन करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस उप-योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 50 हजार से लेकर एक लाख की आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कुल 19 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसमें से तीन करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

यह बजट अब शहरी विकास निदेशालय को सौंपा जा चुका है और इसका उपयोग जिलाधिकारियों के माध्यम से शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने में किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग करके मानकीकृत आधार मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र, मास्टर प्लान और शहरी भू-पोर्टल विकसित किए जाएंगे। राज्य के जिन शहरों को इस मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, वे

हैं: श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, विकास नगर, लक्सर, बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गोपेश्वर, टनकपुर,रामनगर, खटीमा, नगला, कोटद्वार, ऋषिकेश, किच्छा, पिथौरागढ़, बाजपुर और डोईवाला।

केदारनाथ : यात्रियों के लिए नहीं हुई अभी घोड़े खच्चरों की बुकिंग

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब घोड़े-खच्चर सामान लेकर केदारनाथ जाने लगे हैं। हालांकि अभी यात्रियों के लिए घोड़े खच्चरों की बुकिंग नहीं हुई है। दो दिनों में 60 घोड़े-खच्चर सामान लेकर केदारनाथ पहुंचे हैं। इधर, घोड़े-खच्चरों की आवाजाही से स्थानीय लोगों के साथ ही केदारनाथ में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। केदारनाथ पैदल मार्ग में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से केदारनाथ के लिए घोड़े-खच्चरों की आवाजाही बंद हो गई थी। यात्रा के लिए पंजीकृत यूपी और अन्य जनपदों के अधिकांश घोड़े-खच्चर वापस लौट गए हैं। जबकि स्थानीय लोगों के घोड़े-खच्चर ही यहां सेवाएं देने को उपलब्ध है। इनकी संख्या भी वर्तमान में करीब दो सौ के आसपास हैं। करीब 4 सप्ताह बाद घोड़े-खच्चरों की आवाजाही से राशन, गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान केदारनाथ पहुंचने लगा है।

युवाओं में बढ़ रहा है कोलन कैंसर का खतरा, ये लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं टेस्ट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : हाल के कुछ सालों में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक चौंकाने वाला ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है. युवाओं में कोलन कैंसर होने की तादाद बढ़ती जा रही है. परंपरागत रूप से इससे बुजुर्ग या मिडिल एज के लोगों को परेशान करने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन 50 साल से कम उम्र के लोगों में इसके मामलों में वृद्धि ने मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को अलर्ट कर दिया है. हालांकि इस इजाफे के सटीक कारण अभी भी साफ नहीं हैं, सीके बिड़ला हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नीरज गोयल ने बताया कि कोलन कैंसर के कुछ लक्षणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

बाउल हैबिट्स में अचानक बदलाव, खास तौर पर हाल ही में शुरू हुआ कब्ज, कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है. जबकि कब्ज आम है और अक्सर डाइट, टेंशन या डिहाइड्रेशन के कारण होता है, लगातार या बिगड़ता हुआ मामला ट्यूमर के कारण कोलन में रुकावट का संकेत हो सकता है. ये खास तौर से चिंताजनक है अगर कब्ज के साथ पेट में दर्द या मल में खून जैसे अन्य लक्षण भी हों. जो युवा ऐसे कब्ज का सामना कर रहे हैं जिसका सही कारण पता नहीं चल रहा है, उन्हें मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

एनीमिया रेड ब्लड सेल्स की कमी से पहचाना जाता है, ये एक और लक्षण है जो कोलन कैंसर का संकेत दे सकता है, खासकर जब खून की कमी के असल कारणों का पता न हो. यह स्थिति अक्सर ट्यूमर से क्रोनिक ब्लड लॉस के कारण विकसित होती है, जो तुरंत दिखाई नहीं दे सकती है. एनीमिया के लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस की तकलीफ और त्वचा का पीला होना शामिल हैं. अगर कोई युवा बिना किसी ठोस कारण के एनीमिया से पीड़ित है, जैसे कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या सही डाइट की कमी, तो डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है. ब्लड टेस्ट और इमेजिंग सहित जरूरी जांत, एनीमिया के सोर्स की पहचान करने और ये निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या कोलन कैंसर एक फैक्टर है.

अगर आपका वेट लॉस बिना किसी ठोस वजह के हो रहा है तो ये कई तरह के कैंसर का इशारा है, जिसमें कोलन कैंसर शामिल है. अगर कोई यंग एडल्ट अपनी डाइट या एक्सरसाइड की आदतों में बदलाव किए बिना काफी मात्रा में वजन कम करता है, तो आगे की जांच करना जरूरी है. कैंसर कोशिकाएं शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदल सकती हैं, जिससे इंसान के सामान्य रूप से खाने पर भी वजन कम हो सकता है. इसके अलावा कोलन में ट्यूमर के कारण पीड़ित व्यक्ति को जल्दी पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है या उसकी भूख कम हो सकती है, जिससे वजन कम होने लगता. वजन में किसी भी अचानक या बिना साफ कारण के बदलाव के बारे में हेल्थकेयर एक्सपर्ट से चर्चा की जानी चाहिए, खासकर अगर पेट में दर्द या बाउल हैबिट्स में बदलाव जैसे अन्य लक्षण भी हों.

लगातार और बिना किसी ठोस वजह के पेट दर्द होना कोलन कैंसर का आम लक्षण हैं. ये दर्द हल्की परेशानी से लेकर गंभीर ऐंठन तक हो सकता है और ये अन्य पाचन समस्याओं जैसे कि सूजन, गैस या बाउल हैबिट्स में बदलाव से जुड़ा हो सकता है. दर्द अक्सर आंत को बाधित करने वाले ट्यूमर या आस-पास के सेल्स में कैंसर फैलने के कारण होता है. युवा जो नए या बिगड़ते पेट दर्द को महसूस करते हैं, खासकर जब अन्य चेतावनी संकेतों के साथ, इसे एक मामूली समस्या के रूप में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आप शुरुआती टेस्ट कराएंगे तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है.

यूपी के इस मार्केट में हैं 3500 कपड़े की दुकान, 20 रुपए में मिलता है लेडीज सूट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सहारनपुर 28 अगस्त : यूपी में सहारनपुर की रायवाला कपड़ा मार्केट एशिया की नंबर वन कपड़ा मार्केट मानी जाती है. यहां पर लगभग 3500 से अधिक दुकानें हैं. पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली से लोग यहां कपड़ा खरीदने आते हैं. इस मार्केट की शुरुआत 1947 के बाद हुई थी।

पाकिस्तान से आने के बाद वहां के व्यापारियों ने रोजी-रोटी कमाने के लिए सहारनपुर में शरण ली थी. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सहारनपुर में फड़ लगाकर जीविका का एक साधन शुरू किया था. उन्होंने छोटे स्तर पर यहां से कपड़ा व्यापार शुरू किया था, जो कि आज पूरे एशिया में मशहूर है। वहीं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कपड़ा मार्किट के मुख्य संरक्षक राधेश्याम नारंग बताते हैं कि सहारनपुर का कपड़ा मार्केट दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. 1947 के बाद पाकिस्तान से विभाजन के दौरान अपना सब कुछ लुटाकर सहारनपुर पहुंचे लोगों ने अपना छोटे स्तर पर कपड़ों के टुकड़ों से व्यापार शुरू किया था. इस कपड़ा मार्केट की शुरुआत लेडीज कपड़ों से हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी तरह के यहां पर कपड़े मिलने शुरू हो गए. पूरे भारत की मंडियों में सहारनपुर का रायवाला कपड़ा मार्केट सस्ते दाम में कपड़ा बेचने के नाम से मशहूर था. सहारनपुर से माल पूरे देश में जाता है.

मार्केट में 3500 से अधिक हैं दुकानें

कपड़ा मार्केट के अध्यक्ष राधेश्याम नारंग बताते हैं कि आजादी के बाद विकसित हुई. इस रायवाला कपड़ा मार्केट का विस्तार धीरे-धीरे बढ़कर आज बहुत बड़ा हो चुका है. अब रायवाला कपड़ा मार्केट में 3500 से अधिक दुकानें हैं, जो देश के बड़े-बड़े राज्यों में प्रसिद्ध हो चुकी हैं.राधेश्याम नारंग ने बताया कि 1949 के बाद इस मार्केट का आर्थिक विस्तार बहुत बड़ा हुआ है. जिसके कारण देश ही नहीं बल्कि इस बाजार की प्रसिद्धि एशिया तक फैली हुई है. इस कपड़ा मार्केट में 20 रुपए से लेडीज सूट शुरू हो जाते हैं. यह बाजार शुरू से ही कपड़े के लिए जाना जाता है, लेकिन बाद में इस बाजार को लेडिज सूट के लिए प्रसिद्धि मिली.

किसान की बेटी ने किया कमाल, बिना कोचिंग UPSC में हासिल की 23वीं रैंक, बनी IAS अफसर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : गरीबी से अमीरी तक तक का सफर तय करना काफी कठिन होता है. इसलिए ऐसी सफलता भरी कहानियां बेहद प्रेरणादायक होती हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की अटूट शक्ति का प्रमाण होती हैं. ऐसी ही एक सफलता की कहानी IAS तपस्या परिहार की है, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में बिना किसी कोचिंग की मदद के ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल की। एक साधारण से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली तपस्या के पिता विश्वास परिहार एक किसान थे और उनके चाचा विनायक परिहार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनकी दादी देवकुंवर परिहार, जो नरसिंहपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी थीं, उन्होंने भी उनके UPSC के सपने को पूरा करने में उनका साथ दिया। तपस्या ने केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी की और पुणे में इंडियन लॉ सोसायटी के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. इसके बाद, वह अपनी यूपीएससी की यात्रा शुरू करने के लिए दिल्ली चली आई। उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोचिंग भी जॉइन की, लेकिन अपने पहले प्रयास में वह

प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाईं. लेकिन अडिग आत्मविश्वास के साथ साल 2017 में उन्होंने बिना कोचिंग के दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल कर सिविल सेवा परीक्षा पास की.IAS बनने के बाद तपस्या परिहार ने IFS अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी की, जो पहले तमिलनाडु कैडर में तैनात थे. शादी के बाद, वह अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए मध्य प्रदेश कैडर में ट्रांसफर हो गए, जो उसी कैडर में तैनात हैं.

लोगों के बीच में रहता है ये शेर, बन चुका है इलाके की पहचान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : एक ऐसा शेर जो लोगों के बीच में रहता है. जी हां उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक ऐसा ही शेर है जो चलते-फिरते लोगों के बीच में खड़ा रहता है. इस शेर से लोगों को न ही खतरा है न ही लोग इससे डरते हैं. ये शेर लैंडमार्क तक बन चुका है. तो हम किसी असली शेर की नहीं बल्कि अल्मोड़ा के लाला बाजार में स्थित लोहे के शेर की बात कर रहे हैं. यहां पर शेर की आकृति देखने को मिलती है जो एक लैंडमार्क के रूप में जानी जाती है. यदि लोग अल्मोड़ा में किसी को भी बुलाते हैं तो तो वह लोहे के शेर के पास का पता बताते हैं और वह व्यक्ति इस लोहे के शेर के पास आ जाता है. कभी-कभी कोई रास्ता भटक जाए, तो इसी जगह के बारे में बात कर वह इस जगह में आ जाता है.

स्थानीय निवासी कल्याण मनकोटी ने बताया कि लोहे का शेर हमारी विरासत का हिस्सा बन चुका है. हर जगह की कोई न कोई चीज उसकी पहचान की वजह से जानी जाती है, वैसे ही अल्मोड़ा का लोहे का शेर भी आज एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है. अल्मोड़ा में आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े इस लोहे के शेर को पहचानते हैं और यह एक लैंडमार्क भी बन चुका है. किसी को बुलाना हो या फिर कोई रास्ता भटक जाए तो इस लोहे के शेर का पता बताकर लोग यहां पर पहुंच जाते हैं. बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस लोहे के शहर के बारे में जानकारी लेते हैं.नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा के लाल बाजार में स्थित लोहे का शेर आज अपनी ऐतिहासिकता को लिए हुए है. कई सालों से यह शेर की आकृति यहां पर बनी हुई है. इस शहर को लेकर लोगों की अलग-अलग बातें और कहानी आती रहती हैं पर इसकी कोई भी सटीक जानकारी नहीं है. आज अल्मोड़ा का यह लोहे का शेर एक पहचान बन चुका है. आज किसी का इंतजार करना हो या फिर किसी को बुलाना हो तो इस लोहे के शेर का पता बताया जाता है.

उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली नियुक्ति, सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 28 अगस्त : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ) इंस्टीट्यूट में 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अस्टिंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी इस चुनौती को साकार रूप देकर राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्य स्थल पर नवाचार का प्रयोग करेंगे। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलायेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और रोजगारपरक शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।

राज्य सराकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में। पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्त्राखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में लिए गये अनेक फैसलों को मॉडल के रूप में पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। युवा कर्णधारों को सही दिशा देने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टप के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।

शोध को बढ़ावा देने के लिए शोद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 05 हजार छात्रों के प्लेसमेंट का भी लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सविता कपूर, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रो. देवेन्द्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

पौड़ी में भाजपा 30 तक चलाएगी सदस्यता अभियान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी। भाजपा के सांगठनिक जनपद पौड़ी की तीन विधान सभाओं के 14 मंडलों में सदस्यता अभियान को लेकर 30 अगस्त तक मंडल कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अभियान के जिला संयोजक संपत रावत ने भाजपा जिलाध्यक्ष सुषमा रावत से रायशुमारी के बाद समस्त मंडलों के कार्यशालाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। साथ ही सदस्यता अभियान प्रतिनिधि, विधान सभा विस्तारक प्रभारी व मुख्यवक्ता भी तैनात कर दिए हैं।

जिला संयोजक संपत रावत ने बताया कि जिले की विधानसभा चौबट्टाखाल के बीरोंखाल में 30 अगस्त को मंडल कार्यशाला होगी। यहां अभियान प्रतिनिधि नरेंद्र डंडरियाल व विधानसभा विस्तारक प्रभारी राय सिंह नेगी होंगे। एकेश्वर में जिला महामंत्री शशि रतूड़ी, सतपुली में ऋषि कंडवाल, बीरोंखाल में पुष्कर जोशी व पोखड़ा में डा. मनमोहन घिल्डियाल मुख्य वक्ता होंगे। विधानसभा पौड़ी के अगरोड़ा में 28, पौड़ी नगर, पौड़ी ग्रामीण व कल्जीखाल में 29 और कोट में 30 अगस्त को कार्यशाला होगी।

यहां अभियान प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख कोट पूर्णिमा नेगी व विधानसभा विस्तारक प्रभारी मातवर नेगी रहेंगे। पौड़ी नगर व अगरोड़ा में शशि रतूड़ी, पौड़ी ग्रामीण में जिलाध्यक्ष सुषमा रावत, कल्जीखाल में दिगंबर नेगी, कोट में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगत किशोर बड़थ्वाल मुख्य वक्ता होंगे। बताया कि विधानसभा श्रीनगर के पाबौ, थलीसैंण और खिर्सू मंडल में 28, पैठाणी और श्रीनगर में 29 अगस्त को मंडल कार्यशाला आयोजित होगी। जहां मैत्री प्रकाश अभियान प्रतिनिधि और मातवर रावत विधानसभा विस्तारक प्रभारी होंगे। श्रीनगर और खिर्सू मंडल में जिला संयोजक संपत रावत, पाबौ में मातवर रावत, पैठाणी में राजेंद्र रौथाण और थलीसैंण में मैत्री प्रकाश मुख्य वक्ता रहेंगे।

पिंडर घाटी को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे

चमोली। थराली के पूर्व विधायक डॉ.जीतराम ने मंगलवार को पिंडर घाटी को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। साथ ही मोटर मार्गों की स्थिति को दुरुस्त करने, बाढ़ सुरक्षा के कार्य करने, क्षतिग्रस्त पुलों का जल्द से जल्द निर्माण करने की मांग की हैं। कुलसारी स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली नंदा लोकजात यात्रा शुरु हो चुकी हैं लेकिन यात्रा मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हैं। प्राणमती नदी पर एक वर्ष पहले आई आपदा में कई लोग घर से बेघर हो गए थे। पैदल और मोटर पुल भी बह चुके थे। साल भर बाद भी पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। डॉ. जीतराम ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में आज तक एमएससी और बीएड की कक्षाएं संचालित नहीं की गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संजीदा नहीं हैं वही जनता मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन को विवश है।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ की चार आन्तरिक सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रदान की रूपये 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के जुलपाता से भटेड़ी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रूपये 29.97 लाख, भटेड़ी से सिरोड़ी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रूपये 44.42 लाख तथा मडसौन से डुगराकोट इण्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रूपये 17.94 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के ग्राम सभा बार्मों से हाई स्कूल तक आंतरिक सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए भी रूपये 23.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ़ की कुल 04 आन्तरिक सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रूपये 1.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने डी0ए0वी0पी0जी0 कॉलेज के बहुउद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण तथा आवश्यक उपकरणों के लिए प्रदान की रुपये 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर के अंतर्गत अशासकीय डी0ए0वी0पी0जी0 कॉलेज, देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक उपकरण एवं सिंथेटिक टर्फ सहित प्रकाश व्यवस्था एवं फाल्स सीलिंग लगाए जाने के लिए रुपये 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदान की गई है।

खराब प्रर्दशन करने वालों पर होगी कार्रवाई: जावलकर

देहरादून। कॉपरेटिव बैंकों में सही काम न करने वाले बीमार ब्रांच मैनेजरों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने मंगलवार को राज्य सहकारी बैंक कैंप कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंकों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जो कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त दी जाए। सचिव सहकारिता ने सभी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सेवाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ करने भी निर्देश दिए। ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैंक में बढ़ रही एनपीए की समस्या पर खास ध्यान देते हुए, एनपीए वसूली में कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की 15 में से 12 शाखाएं लाभप्रद स्थिति में हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे एनपीए में 4.08 प्रतिशत की कमी आई है। सचिव जावलकर ने प्रबंध निदेशक को सहकारी आवास ऋण की पेशकश जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकों में खाते खोलने के लिए आकर्षित करने को अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए कि बैंक की सेवाएं अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें। ग्राहकों को बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। समीक्षा बैठक में जनरल मैनेजर मुकेश महेश्वरी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरएस रैना, आकांक्षा कंडारी, नेहा कांत, पंकज बमेटा आदि अधिकारी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सीएम से मिला राज्य आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल

देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जारी शासनादेश में संशोधन की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला। इस दौरान राज्य निर्माण आंदोलनकारी एवं समाजसेवी मोहन सिंह खत्री ने कहा कि 2009-10 में सरकार की ओर से दो शासनादेश जारी किए गए थे। इनके माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुवाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण के चिह्नित आंदोलनकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि लेकिन ये सुविधा राजकीय मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उपरोक्त शासनादेशों मे राजकीय मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, राजकीय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, राजकीय हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों को भी शामिल कर दिया जाता है, तो मरीजों को अधिक सुविधा मिलेगी। सीएम ने इस बाबत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मौके पर जगमोहन सिंह नेगी, अशोक वर्मा, प्रदीप कुकरेती, चंद्रकिरण राणा, मोहन रावत, मनोज नौटियाल, रविंद्र सोलंकी, राजीव तलवार, गौरव खंडूड़ी, पूरण सिंह लिंगवाल आदि मौजूद थे।

दून वैली और इंडियन पब्लिक स्कूल सेमीफाइनल में पहुंचे

देहरादून। एसपी सिन्हा मेमोरियल अंडर-19 इंटर स्कूल फुटबाल चैंपियनशिप में इंडियन पब्लिक और दून वैली स्कूल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला देहरादून में मंगलवार को मुकाबले खेले गए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच दून ग्रामर स्कूल और इंडियन पब्लिक स्कूल के बीच खेल गया। आखरी समय तक दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाई। पेनल्टी शूट में इंडियन स्कूल 2-1 के अंतर से विजेता रहा। इंडियन स्कूल की ओर से दक्षवीर, संजीत, दून ग्रामर की तरफ से आर्यन ने गोल किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में दून वेली इंटरनेशनल स्कूल ने वीएफआरआई को 4-1 के अंतर से शिकस्त दी।

एडीजी ए.पी.अंशुमन सोशल मीडिया को लेकर हुए गंभीर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून,27 अगस्त।ए0पी0 अंशुमान, ADG, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से दोनों परिक्षेत्र, समस्त जनपद प्रभारियों, पुलिस उपाधीक्षक, ऑप्स एवं सोशल मीडिया सेल प्रभारियो के साथ वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक कर जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया प्रमोशन सेल एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के कार्यो की समीक्षा की गयी, जिसमें उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कृष्ण कुमार वी के, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना तथा सुश्री पी रेणुका देवी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-

1. जनपदों में स्थापित सोशल मीडिया सेलों को सक्रिय कर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्त पोस्टों की नियमित रुप से मॉनिटरिंग करायी जाये तथा भ्रामक पोस्टों पर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत S.O.P के अनुरूप तत्काल कार्यवाही की जाये।

2. सोशल मीडिया सेल द्वारा किये जा रहे कार्यों का पुलिस उपाधीक्षक, ऑप्स नियमित रुप से पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें।

3. समस्त जनपद प्रभारी उपरोक्त सैल की जनशक्ति एवं उनके कार्यों का मूल्याकंन करते हुए समीक्षा रिपोर्ट परिक्षेत्र कार्यालय सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जनपद स्तर पर सोशल मीडिया इन्फल्यूएंसर का चिन्हीकरण करते हुए उनके साथ जिला मुख्यालय अथवा थाने स्तर पर गोष्ठी आहूत कर उन्हें सकारात्मक एवं जनजागरूकता विषयक पोस्ट किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।

5. कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले भ्रामक पोस्टों का तत्काल खण्डन किया जाये।

6. सोशल मीडिया पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्टों को हटाये जाने सम्बन्धित कार्यवाही करने एवं टेकडाअन नोटिस जारी करने हेतु शासन स्तर से नामित नोडल पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था को पत्र प्रेषित किये जाने एवं पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत एस0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

7. पुलिस मुख्यालय स्तर से पुलिस कार्मिकों हेतु निर्गत सोशल मीडिया पॉलिसी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जाये। यदि कोई पुलिस कर्मी उक्त पॉलिसी का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सम्पादित कराते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

8. उक्त के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा आज ही पुलिस मुख्यालय स्थित अपराध एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त अनुभागों के कार्यों की समीक्षा कर अनुभाग/शाखा प्रभारियों को कार्यों का समयान्तर्गत निष्पादन किये जाने के निर्देश दिये गये।

पैदल चलना या ट्रेडमिल वॉकिंग सेहत के लिए ज्यादा बेहतर कौन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : सेहतमंद रहने के लिए पैदल चलना सबसे बड़ी एक्सरसाइज में से एक है. इसलिए लोगों को 10 हजार कदम चलने का कहा जाता है. पैदल चलने के लिए न तो किसी उपकरण की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष जगह की. एक दौर था जब लोगों को मजबूरी में चलना ही होता था, लेकिन बदलते परिवेश में सुविधाएं बढ़ गईं और पैदल चलने के लिए समय का अभाव होने लगा. इसका नतीजा यह हुआ कि कई बीमारियां शरीर में आने लगीं. ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी हो गया है.

रिसर्च के मुताबिक, स्नीकर्स पहनकर तेजी से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट पैदल चलने की सलाह देते हैं. इसे करने के लिए जब भी समय हो तो वॉक या जॉगिंग कीजिए. हालांकि, आजकल ज्यादातर लोग पैदल चलने के लिए जिम में उपलब्ध ट्रेडमिल का सहारा लेता लेता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद से पैदल चलना ज्यादा बेहतर है या ट्रेडमिल पर चलना? सेहत के लिए अधिक फायदेमंद कौन? आइए जानते हैं इस बारे में-शारीरिक गतिविधियों में अंतरईटदिश डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्मल वॉक और ट्रेडमिल पर वॉक में शरीरिक गतिविधियां लगभग समान होती हैं. हालांकि, कुछ चीजों में बुनियादी अंतर जरूर है. इसीलिए, पैदल और ट्रेडमिल पर चलने का परिणाम अलग-अलग हो सकता है. दरअसल, जब आप बाहर या पार्क में पैदल चलते हैं तो आप हवा के दबाव के साथ आगे बढ़ते हैं. जब हवा का प्रेशर शरीर पर पड़ता है तो ज्यादा ताकत लगती है. वहीं, ट्रेडमिल पर हवा का कोई दबाव नहीं होता है. इसलिए ट्रेडमिल पर आपके शरीर में सपाट बल लगता है. यही कारण है नॉर्मल वॉक वजन कम करने के लिए ज्यादा कारगर है.ट्रेडमिल के बजाय बाहर घूमना अधिक फायदेमंद है. इससे सेहत को अधिक फायदा होता है. दरअसल, जब आप बाहर घूमते हैं या वॉक करते हैं तो रास्ता उबड़-खाबड़ होता है. पहाड़ों पर चलने में और ज्यादा परेशानी है. इसी तरह पेड़-पौधे, ट्रेल, पशु-पक्षी आदि के साथ का अनुभव भी मिलता है. इस स्थिति में शरीर का अंग-अंग हिलता है. इसमें कदमों की लंबाई, ताल और पैरों की पोजिशन भी अलग-अलग होती है. ट्रेडमिल पर ऐसा नहीं होता. यहां एक ही तरह का मूवमेंट होता है. लेकिन नॉर्मल वॉक में शरीर के अधिकांश मांसपेशियां हिस्सा लेते हैं.

फर्म के कैशियर ने लाखों रुपये अपने खाते में ट्रांसफर किए, केस दर्ज

देहरादून। कारोबारी की फर्म में हिसाब किताब का रिकार्ड रखने के लिए रखे गए कैशियर ने अपने बैंक खाते में 12.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा सात लाख रुपये नगदी लेकर फरार हो गया। मामले में रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि साकिब अंसारी निवासी नई बस्ती, चंदर रोड की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। बताया कि उनकी कबाड़ी बाजार चूना भट्टा में दुकान और कार्यालय है। वह कंस्ट्रक्शन मेटेरियल और हार्डवेयर का भी काम करते हैं। उनकी और उनके भाई की चार फर्म हैं। इनमें हिसाब किताब के लिए शाह फैसल निवासी जैन प्लाट वाणी विहार को बतौर एकाउंटेंट रखा हुआ था। आरोप है कि बीते 10 अगस्त को वह फरार हुआ। इससे पहले एक फर्म के चेक से 6.50 लाख, दूसरी फर्म के चेक से छह लाख रुपये अपने बैंक खाते में जमा कराए। आरोपी फर्म की सात लाख रुपये नगदी भी लेकर फरार हो गया। इसके बाद से आरोपी के मोबाइल बंद भी हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

विधायक दुर्गेश्वर लाल के आवास पर हुए विवाद में दो युवकों पर केस

देहरादून। विधायक दुर्गेश्वर लाल के आवास पर हुए विवाद में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा विधायक के निजी सचिव की तरफ से दर्ज किया गया है। मामले में युवकों की तरफ से भी विधायक के खिलाफ तहरीर दी गई है। नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि घटनाक्रम बीते 25 अगस्त को विधायक हॉस्टल स्थित विधायक दुर्गेश्वर लाल के आवास का है। विधायक के निजी सचिव उमेंद्र आस्टा ने दी तहरीर में कहा कि घटना के दिन शाम करीब चार बजे विधायक कक्ष संख्या छह में बैठे हुए थे। वहां कुलदीप पंवार और अतुल पंवार नाम के दो युवक घुस आए। आरोप है कि दोनों ने पीएमजीएसवाई के टेंडर दिलाने का दबाव बनाया। विधायक ने नियमानुसार टेंडर आवंटन की बात कही। आरोप है कि तब दोनों ने गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस को फोन किया तो दोनों वहां से भाग गए। थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

शेयर ट्रेडिंग का झांसा दे 43 लाख की ठगी में शामिल आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम थाना देहरादून पुलिस ने सूरत गुजरात से साइबर धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी रुड़की, हरिद्वार निवासी पीड़ित के साथ 43 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। आरोपी से जुड़ा गैंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर स्टॉक ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश की पोस्ट डालकर लोगों को ठगते हैं। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि रुड़की निवासी पीड़ित की शिकायत बीते जून महीने में केस दर्ज दिया गया। पीड़ित को इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन दिखाई दिया। उसमें शेयर ट्रेडिंग में कमाई का झांसा दिया गया। पोस्ट में दिए गए लिंक के जरिए पीड़ित एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। इसके बाद आरोपी गैंग ने पीड़ित को अच्छा मुनाफ कमाने का लालच दिया। एक वेबसाइट देते हुए उस पर लॉगइन बनाने को कहा। उसमें पेन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी अपलोड कराई गई। इसके बाद शेयर मार्केट और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर पीड़ित से कुल 43.11 लाख रुपये ठगे गए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच की। इस दौरान ठगी में शामिल समीर दिलावर पटेल (20 वर्ष) निवासी सूरत, गुजरात को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, बैंक खाते का एसएमएस अलर्ट नंबर और चेक बुक बरामद हुई। आरोपी मिले बैंक खातों में ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है।

हरिद्वार हाईवे पर कट को खोलने की मांग

देहरादून। देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर कैलाश अस्पताल से विवेकानंद स्कूल के बीच कट बंद करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को एसएसपी को ज्ञापन भेजकर कट पर लगाए बैरकेडिंग हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि कट बंद करने से यहां यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घूमकर आना पड़ रहा है। जनहित में शीघ्र ही कट पर लगाए गए बैरेकेडिंग हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में डोईवाला विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी गौरव सिंह, पूर्व उप प्रधान जितेंद्र कुमार, निवर्तमान पार्षद सचिन थापा, वार्ड अध्यक्ष गणेश डंडरियाल, पूर्व प्रधान सुशीला देवी, इंटक के प्रदेश सचिव नीरज भंडारी, सुनील डोभाल, एसएस असवाल, चमन लाल आदि मौजूद रहे।

पुरानी एसीपी को लागू न किए जाने पर कर्मचारी नाराज

देहरादून। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने पुरानी एसीपी समेत अन्य मांगों के निस्तारण को दबाव तेज कर दिया है। मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन को चार सितंबर को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वार्ता को बुलाया है। संगठन के संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट ने बताया कि कर्मचारी शिक्षकों की लंबित 35 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं हो पाया है। इसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। अधिकतर मांगों का निस्तारण शासन स्तर पर लंबित है। इन सभी का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना है। इन मांगों के निस्तारण को मुख्य सचिव की ओर से आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा सत्र के बाद सचिवालय में एक विस्तृत बैठक होगी। इसमें वित्त, कार्मिक, न्याय समेत सभी सम्बन्धित विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। महामंत्री अशोक राज उनियाल ने कहा कि चार सितंबर को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में मजबूती के साथ कर्मचारियों का पक्ष रखा जाएगा। कर्मचारियों की सबसे अहम मांग पुरानी एसीपी का लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। 10, 16 और 20 वर्ष पर एसीपी का लाभ दिया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4200 ग्रेड वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड में आ रही परेशानियों को दूर किया जाए। केंद्र के समान हाउस रेंट का लाभ देने का आदेश किया जाए। कार्मिकों को जनपद, मंडल स्तर पर स्थानांतरण की छूट दी जाए। राजकीय वाहन चालकों को 4800 ग्रेड वेतन देने के फैसले में देरी न की जाए। राजकीय शिक्षकों को प्रवक्ता के पद पर राजपत्रित घोषित किया जाए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का आमंत्रण किए जाने का भी आदेश जारी किया जाए।

जनधन : भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति सशक्तीकरण के 10 साल और भविष्य

विशेष आलेख

देहरादून , 28 अगस्त , प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की 10वीं वर्षगांठ है। यह एक बुनियादी समावेशन परियोजना है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था में वित्तीयकरण, औपचारिकरण और डिजिटलीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता की है। आज जबकि 53 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 80% वयस्कों का किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में खाता है। यह 2500 अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक मानदंडों की तुलना में कहीं अधिक है। बैंक खाते खोले जाने से महिलाओं (जनधन खातों में 55% हिस्सेदारी) के साथ-साथ पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों को भी सशक्त बनाने में मदद मिली क्योंकि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हिस्से की सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे उन्हें प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग किया।

भारत ने तीन महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ जोड़कर अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कार्यनीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया जिससे यह संभव हुआ जैसे कि जैम ट्रिनिटी और बैंक खाता (जनधन) इस ट्रिनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसके अतिरिक्त डिजिटल पहचान (आधार) और मोबाइल नंबर भी इसका हिस्सा हैं। डीबीटी के उपयोग के माध्यम से इसने राजकोषीय बचत को बढ़ावा दिया। मार्च, 2023 तक संचयी बचत रुपए 3.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है क्योंकि सरकार लगभग रुपए 7 लाख करोड़ सालाना अंतरित करती है। ₹बैंक रहित₹ लोगों के पास अब बैंक खाते तक पहुँच है और उन्हें निःशुल्क रूपे कार्ड प्रदान किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिली है। डीबीटी के 65% से अधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में जनधन द्वारा निभाई गई भूमिका का संकेत मिलता है।

जनधन की शुरुआत के दो साल बाद, अप्रैल, 2016 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस या यूपीआई नामक एक तत्काल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई जिसने खुदरा डिजिटल भुगतानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से 1200 करोड़ मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की है। भुगतान/वित्तीय लेनदेन के मामले में यूपीआई क्रांति के लिए बुनियाद तैयार करके इसमें जनधन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जनधन और यूपीआई ने मिलकर एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण का बढ़ावा दिया है जो डेटा एक्सेस या अंतर-संचालनीयता के विस्तारीकरण बनाने में सहायता प्रदान करता है जिसका लाभ वित्तीय संस्थानों द्वारा छोटे टिकट की उधारी की ऋण हामीदारी के लिए लिया जा सकता है। इसने फिनटेक जगत में नवोन्मेषिता को भी बढ़ावा दिया है क्योंकि वे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर 2014 में जनधन से शुरू हुए सुधार उसके बाद 2016 में यूपीआई और फिर 2017 में जीएसटी ने भारत को ₹विश्व में सबसे बड़ा निजी डेटा-कैशर वाला ₹डेटा संपन्न देशर बनाने में सहायता प्रदान की है जिसने एआई क्रांति को सशक्त किया है।

आगे की राह?

भारत, वर्तमान में विश्व में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ वृद्धि उचित इकोसिस्टम के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसकी नींव 2014 में जनधन सुधार के माध्यम से रखी गई थी। इस डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम में नवीनतम जुड़ाव यूएलआई (यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस) है जो विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उधारकर्ताओं को जिनकी ऋण मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है उन्हें परेशानी रहित ऋण प्रदान करता है। यह कृषि, एमएसएमई आदि के क्षेत्र में छोटे उधारकर्ताओं के लिए एक वित्तीय क्रांति होगी। भूमि रिकॉर्ड, इकाई का पंजीकरण, सी-केवाईसी, क्रेडिट इतिहास, वित्तीय पण्यावर्त आदि जैसे बेहतर डिजिटल रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों की परिचालन लागत को कम करने के साथ-साथ निर्धारित समय अवधि और मानवीय भूल को कम कर देंगे। आरबीआई गवर्नर के अनुसार, ₹जैम-यूपीआई-यूएलआई की 'नई ट्रिनिटी' भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगी₹।

बैंकिंग प्रणाली, पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों हेतु छोटे-टिकट वाले उत्पादों के प्रावधान के माध्यम से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करके उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हम डीबीटी प्राप्तियों के आधार पर क्रेडिट इतिहास/क्षमता के साथ सूक्ष्म-ऋण, माइक्रो-इंश्योरेंस (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के लिए पृथक और एक साथ) के साथ-साथ कम मूल्य के सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से सूक्ष्म-निवेश विकल्पों, सरकारी बॉन्ड में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी के लिए आरबीआई के पोर्टल के माध्यम से कम टिकट निवेश जैसे उत्पादों पर विचार कर सकते हैं। बैंकों के लिए, बाद वाले विकल्प विभिन्न निवेश विकल्पों को ढूढ़ने के इच्छुक युवा आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं को समझने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है।

निष्कर्ष के तौर पर जनधन के कार्यान्वयन के एक दशक बाद ये सुधार डिजिटल वित्त क्रांति को बढ़ावा देकर विकसित भारत@2047 बनने की दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग को निरंतर प्रशस्त कर रहा है। जनधन इस बात का उदाहरण है कि देश के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण लोगों और समाज को कितना प्रभावित कर सकता है। 'सभी के लिए बैंक खाता' के उद्देश्य से जनधन अब भारत के लिए एक वित्तीय और डिजिटल क्रांति का रूप ले रहा है।

पौड़ी पुलिस ने कंडोलिया मैदान में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव

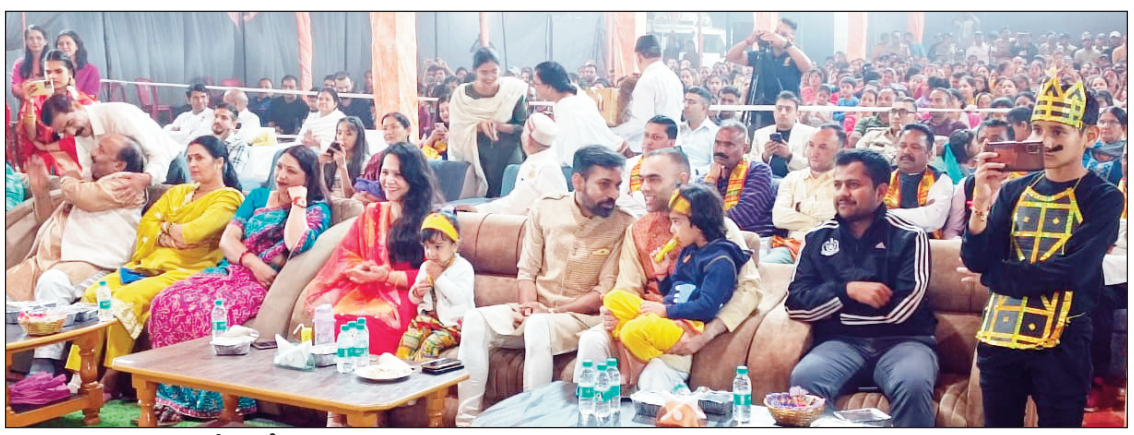

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी 28 अगस्त : विशिष्ठ अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष शान्ति देवी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी,जिलाधिकारी पौड़ी डा0 आशीष चौहान एवम्-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने दीप जलाकर किया श्री कृष्णाजन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ।प्रसिद्ध जौनसारी लोकगायक मनोज सागर व उनकी टीम द्वारा लोक गीतों व लोकनृत्यों की दी गयी भव्य प्रस्तुति, दर्शकगण हुये झूमने पर मजबूर।

कृष्ण जन्माष्टमी पौड़ी पुलिस द्वारा कण्डोलिया मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का शुभारम्भ विशिष्ठ अतिथि मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, मा0 विधायक पौड़ी राजकुमार पौरी,जिलाधिकारी पौड़ी डा0 आशीष चौहान,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह व डीएफओ पौड़ी स्वप्निल अनिरुद्ध द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात पुलिस परिजनों, विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम, रंगारंग एवं मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।

इस शुभ अवसर पर उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लोकगायक मनोज सागर व उनकी टीम द्वारा गढ़वाली, कुमांऊनी व जौनसारी लोक गीतो व लोकनृत्यों की भव्य प्रस्तुति दी गयी जिससे दर्शकगण झूमने पर मजबूर हो गये। कार्यक्रम के दौरान सिद्धि विनायक डान्स ग्रुप कोटद्वार द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की नृत्य द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गयी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी 'यमराज की पेशी' नाटक में किए गए जीवंत अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया और दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने सम्बोधन में उपस्थित मुख्य अतिथिगणों, पत्रकार बन्धुओं, कलाकारों तथा उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया व जनपद वासियों को जन्माष्टमी के पर्व पर अपनी शुभकामनाएं दी गयी।

गेहूं-धान छोड़कर इस फसल की कर रहे खेती, 1 एकड़ खेत से 4 लाख मुनाफा, किसान मालामाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : इन्ही फसलों में से एक बांस की फसल है, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहती है. क्योंकि, ये कई चीजों में बांस का इस्तेमाल होता है. खास तौर पर फर्नीचर जैसी चीजों में इसकी डिमांड काफी होती है. तो वहीं इससे साज सज्जा के सामान भी खूब बनाए जाते हैं. इसके गिलास और लकड़ी के अन्य बर्तन भी बनाए जाते हैं. तो वहीं कुछ किसान इसकी खेती कर शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं.

बाराबंकी जिले के सैदाहा गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान संग्राम सिंह बांस की खेती कर अच्छा कमाई कर रहे है, जिससे उन्हें इस खेती से 4 लाख रुपये तक का मुनाफा हो रहा है.बांस की खेती कर रहे किसान संग्राम सिंह ने Local18 को बताया पहले धान, गेहूं, मेंथा, सरसों आदि की खेती करते थे. लेकिन फिर तुलसी की खेती शुरू की. फिर उन्होंने सोचा क्यों न ऐसी खेती की जाए, जिसमें मजदूर और लागत भी कम लगे. फिर बांस की खेती के बारे में पता चला. फिर उन्होंने मध्य प्रदेश से बाल कुआं वैरायटी का बांस का पौधा मंगवाया, जो उन्हें ₹56 रुपया पर पौधा मिला.इन्होंने एक एकड़ की जमीन पर करीब 600 पौधे लगाए, जिसमें उनकी लागत करीब एक एकड़ में 40 हजार रुपये आई. वहीं, मुनाफा करीब चार लाख रुपए तक हुआ. इसको एक बार लगाने के बाद इसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं डालना पड़ता है.उन्होंने बताया कि बांस की खेती करना काफी आसान है. सबसे पहले इसके पौधे को नर्सरी से लाएं. इसके बाद इसकी रोपाई कर दें. इसमें यह ध्यान दें कि रोपाई के लिए गड्ढा 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा हो. वहीं, इसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत नहीं होती है. बस ध्यान रहे कि मिट्टी बहुत अधिक रेतीली न हो. रोपाई के बाद अब इसमें गोबर से तैयार खाद का इस्तेमाल करें. वहीं पौधे लगाने के बाद इसकी सिंचाई करनी पड़ती है. इसके पौधे लगाने के तीन महीने बाद पौधे की ग्रोथ होने लगती है. वही, 4 साल में यह पूरी तरह तैयार हो जाता है.

उत्तराखंड में आईएसएस अधिकारियों का ट्रांसफर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 28 अगस्त , उत्तराखंड में मंगलवार 27 अगस्त को 6 आईएएस के तबादले हुए हैं. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी के संयुक्त मजिस्ट्रेट को बदला गया है. वहीं वेटिंग पर बैठे तीन आईएसएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा देहरादून के तीन पीसीएस अधिकारियों को भी बदला गया है. अल्मोड़ा की संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस वरुणा अग्रवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर बनाया गया है. वहीं, पिथौरागढ़ के संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस आशीष कुमार मिश्रा को संयुक्त मजिस्ट्रेट हरिद्वार बनाया गया है. इसके अलावा संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी आईएएस अनामिका को संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून बनाया गया है.

आईएएस दीपक रामचंद्र सेठ को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी बनाया गया. वहीं आईएएस राहुल आनंद को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत बनाया है. आईएएस अशिमा गोयल को संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल बनाया गया है. ये तीनों आईएएस अधिकारी वेटिंग लिस्ट में थे.उधर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने भी अपने जिले से तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. चकराता उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे योगेश मेहरा को उप जिलाधिकारी डोईवाला बनाकर गया है. वहीं अपर्णा ढौंडियाल को डोईवाला से चकराता उपजिलाधिकारी बनाकर भेजा गया है.

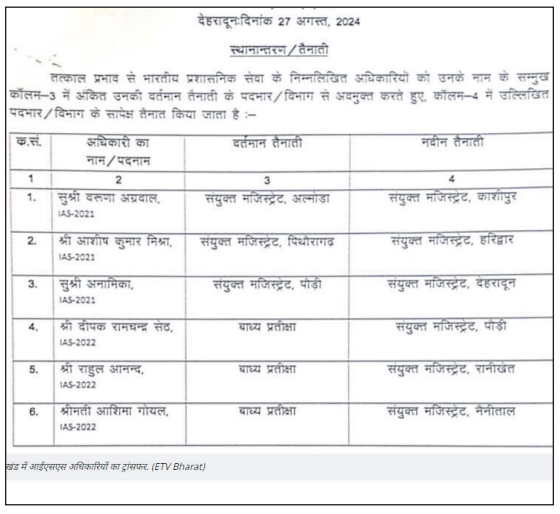

देहरादून:दिनांक 27 अगस्त, 2024

स्थानान्तरण/तैनाती

तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित उनकी वर्तमान तैनाती के पदभार/विभाग से अवमुक्त करते हुए, कॉलम–4 में उल्लिखित पदभार/विभाग के सापेक्ष तैनात किया जाता है :–

क.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	सुश्री वरुणा अग्रवाल, IAS-2021	संयुक्त मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा	संयुक्त मजिस्ट्रेट, काशीपुर
2.	श्री आशीष कुमार मिश्रा, IAS-2021	संयुक्त मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ	संयुक्त मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
3.	सुश्री अनामिका, IAS-2021	संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी	संयुक्त मजिस्ट्रेट, देहरादून
4.	श्री दीपक रामचन्द्र सेत, IAS-2022	वाध्य प्रतीक्षा	संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी
5.	श्री राहुल आनन्द, IAS-2022	वाध्य प्रतीक्षा	संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत
6.	श्रीमती आशिमा गोयल, IAS-2022	वाध्य प्रतीक्षा	संयुक्त मजिस्ट्रेट, नैनीताल

खंड में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर. (ETV Bharat)

इसके अलावा गौरी प्रभात को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से हटाकर अब कालसी उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इन तबादलों के बाद कई और आईएएस व आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी लिस्ट जल्द ही जारी होगी.

Aadhaar Card में पता अपडेट करने के लिए नहीं देना कोई डॉक्यूमेंट, ये है पूरा प्रोसेस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : अगर हमसे कोई हमारा आईडी प्रूफ मांगता है तो हमारा सबसे पहला ध्यान आधार कार्ड पर जाता है। आज गैर-सरकारी और सरकारी कामों के लिए भी हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसमें सभी जानकारी सही हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड पर नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ घर का पता भी शामिल होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से आप घर बदल रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन, अगर आप घर का पता अपडेट कर रहे हैं तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इसे अपडेट कर सकते हैं।

एड्रेस अपडेट कैसे करेंआपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in/) पर जाना होगा।इसके बाद लॉग-इन के ऑप्शन में जाकर आधार नंबर और कैप्चा

दर्ज करना होगा।इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें।अब आधार अपडेट के सेक्शन में जाकर Head Of Family (HOF) बेस्ड आधार अपडेट पर क्लिक करें।यहां आपको head of the family का आधार नंबर दर्ज करना है।इसके बाद आपको अपडेशन फीस देनी होगी।अपडेशन चार्ज देना के बाद Head of the family के पास रिक्वेस्ट जाएगी।जैसे ही Head of the family इस रिक्वेस्ट को Allow वैसे ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा।फ्री आधार अपडेटUIDAI ने आधार यूजर्स को फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा भी दी है। आप ऑनलाइन 14 सितंबर 2024 तक फ्री में ऑनलाइन आधार अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि, ऑफलाइन आधार अपडेट करने के लिए आपको चार्ज का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि प्रति अपडेशन का 50 रुपये चार्ज लगता है।

संक्षिप्त खबरें

पेंट कंपनी की डीलरशिप का झांसा दे वकील से सवा दो लाख ठगे

देहरादून। बेटे के नाम पर एशियन पेंट कंपनी की डीलरशिप लेने के झांसे में देहरादून के वकील ठगी का शिकार हो गए। उनकी तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थानाध्यक्ष प्रदीप नेगी ने बताया कि वकील राजेश कुकरेती के साथ एशियन पेंट्स के अधिकारी बनकर 2.25 लाख रुपये ठगी का मामला सामने आया है। वकील का पुत्र पेंट और हार्डवेयर का व्यापार करना चाहता है। उन्होंने बीते 13 अगस्त को एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। 16 अगस्त 2024 को उन्हें एशियन पेंट से मिलती ईमेल आईडी से एक फॉर्म भेजा गया। पंजीकरण शुल्क के रूप में 24,999 रुपये जमा करने को कहा गया। इसके बाद 17 अगस्त को दो लाख रुपये सिक्योरिटी के नाम पर जमा कराए गए। यह रकम दी तो बुकिंग कर आर्डर भेजने के लिए 5.5 लाख रुपये मांगे गए। जिससे वकील को शक हुआ। जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति को संपर्क किया, तो उसका फोन बंद मिला। बाद में उन्होंने एशियन पेंट को मेल किया। जिसमें पता चला कि वह मेल आईडी अधिकृत नहीं थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निर्दलीय विधायक उमेश का बयान गैर जिम्मेदाराना: गरिमा दसोनी

देहरादून। विधानसभा में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान को कांग्रेस ने बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस बयान को विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कहा कि स्पीकर इस मामले में विधायक को लगाए गए आरोपों को साबित करने को निर्देशित करें। मीडिया में जारी बयान में गरिमा दसोनी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। विधानसभा का पटल कोई अखाड़ा नहीं है, जहां कोई भी अपने पुराने लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट करे। कहा कि विधायक के आरोपों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि यदि सरकार गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, तो इससे उमेश कुमार को क्यों परेशानी हो रही है। इससे सरकारी खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके पूरी तरह से ध्वस्त होने की पुष्टि हो रही है। क्योंकि एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पता चल रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के विधायक ऐसे हैं, जो कोई भी धन पशु उन्हें खरीद सके। कहा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली इस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। स्पीकर आरोप लगाने वाले सदस्य से तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें साबित करने को निर्देशित करें।

साहित्य मेरे लिए शौक नहीं जरूरत है: शर्मा

देहरादून। साहित्य मेरे लिए शौक नही जरूरत। इसीलिए जीवन की विविधता के कारण विभिन्न विधाओं में चालीस पुस्तकें लिख सका। यह बात जनकवि व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ अतुल शर्मा ने दून पुस्तकालय व शोध केन्द्र के द्वारा मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम विधाएं अनेक और लेखक एक में अपने संबोधन के दौरान कही। वरिष्ठ पत्रकार डॉ सुशील उपाध्याय व विपिन बनियाल ने उनसे विशेष बातचीत की। उन्होंने कविता संग्रह थकती नहीं कविता, बिना दरवाजे का समय, नदी एक लम्बी कविता, जनगीतों का वातावरण, सींचे नीव आदि के साथ उपन्यास जवाब दावा, दृश्य अदृश्य, नानू की कहानी सहित दो बेहर चर्चित पुस्तक, सीरीज वाह रे बचपन के सात खंड आदि को लेकर अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि इस सीरीज के सात खंड निकाले। जिनमें अस्सी लोगों के बचपन के संस्मरण प्रकाशित हैं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रीय कवि श्रीराम शर्मा प्रेम के समग्र साहित्य पर पांच ग्रंथ सम्पादित किए। जिनका सह संपादन रेखा शर्मा व रंजना शर्मा ने किया है। डॉ सुशील उपाध्याय के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शामिल रहकर जन गीत लिखे। जो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहे। छीन के लेंगे उत्तराखंड, नदी बचाओ आंदोलन को जन गीत दिए। वरिष्ठ पत्रकार विपिन बनियाल ने पूछा कि उनके लिखे नाटक और रंग गीत कौन से हैं। जवाब देते हुए डॉ अतुल शर्मा ने बताया कि नाटकों की पुस्तक प्रकाशित हुई है, उन्नीस नाटक।

रास्ते की जमीन पर मकान बनाकर 72 लाख में बेचा

देहरादून। रास्ता श्रेणी की भूमि पर मकान बनाकर 72 लाख रुपये में बेच दिया गया। मेहूंवाला क्षेत्र में हुए फर्जीवाड़े में बसंत विहार थाना पुलिस ने मां बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ बसंत विहार महादेव उनियाल ने बताया कि बॉबी त्यागी निवासी ऋषि विहार, मेहूंवाला ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी। कहा कि अक्तूबर 2018 में अपनी पत्नी इंदू त्यागी के नाम पर मेहूंवाला स्थित एक मकान 72 लाख रुपये खरीदा। रजिस्ट्री हर्ष गंगवानी पत्नी यशपाल और उनके बेटे शिव गंगवानी की तरफ से करवाई गई। शिकायत के अनुसार फरवरी 2023 में मकान पर लोन लेने के लिए बैंक में आवेदन किया गया। बैंक ने जांच कराकर पीड़ित को बताया कि जिस खसरे पर मकान बनाया गया है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ते की श्रेणी में दर्ज हैं।

16 साल के Gout Gout ने किया कमाल, 100 मीटर की रेस में Usain Bolt का रिकॉर्ड तोड़ने बाल बराबर चुके

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : उसैन बोल्ट को दुनिया के कोने-कोने में जाना जाता है. दिग्गज धावक उसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है. बोल्ट ने यह रिकॉर्ड 2009 में बनाया था. अब 16 साल के धावक गाउट गाउट दिग्गज उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने से लगभग बाल बराबर चूक गए. बोल्ट ने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की थी, वहीं गाउट गाउट ने 10.29 सेकंड में 100 मीटर का रेस खत्म की। बस इसके बाद से ही चारों तरफ ऑस्ट्रेलियाई धावक गाउट गाउट का नाम गूंजने लगा. ऑस्ट्रेलियाई धावक ने ऑस्ट्रेलिया में हो रही क्वींसलैंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह कारनामा किया. वह रेस में अव्वल आए. रेस के दूसरे सबसे तेज धावक गाउट गाउट से करीब 10 कदम पीछे रहे. ऐसा कहा जा सकता है कि गाउट गाउट ने रेस में एकतरफा जीत दर्ज की.

कौन हैं गाउट गाउट ?बता दें कि गाउट गाउट का जन्म 29 दिसंबर, 2007 को

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था. उनके माता-पिता सूडानी हैं. हालांकि गाउट गाउट के माता-पिता ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए थे. वह 15 साल की उम्र में भी कमाल कर चुके हैं. 2023 ऑस्ट्रेलिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें अंडर-18 की 200 मीटर रेस के फाइनल में जीत हासिल की थी. जनवरी में गाउट गाउट ने 200 मीटर की रेस 20.69 सेकंड में पूरी थी.

अप्रैल 2024 में गाउट गाउट ने उसैन बोल्ट से उनकी तुलना किए जाने पर बात की थी. फॉक्स स्पोर्ट्स ने उनके हवाले से लिखा था, ₹यह बहुत अच्छा है क्योंकि उसैन बोल्ट जाहिर तौर पर अब तक के सबसे महान एथलीट हैं. उनसे तुलना होना एक शानदार एहसास है. मैं गाउट गाउट हूं, तो मैं अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर मैं उनके लेवल तक पहुंच पाया तो यह बड़ी कामयाबी होगी.

सेना की महिला नर्स को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख ठगे

देहरादून। भारतीय सेना की महिला नर्स को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपये से अधिक रकम ठग ली। आरोपियों ने महिला का मोबाइल नंबर बंद किए जाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। वीडियो कॉल में पुलिस वर्दी में बैठे अफसरों ने मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई से जुड़ा बताकर क्लीयरेंस के नाम रकम जमा कराई। महिला की तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैनिक कॉलोनी बालावाला निवासी नीतू कुमारी भारतीय सेना में नर्स की नौकरी करती हैं। नीतू वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत साउथ सूडान में तैनात हैं। हाल में वह 28 दिन की छुट्टी पर देहरादून स्थित अपने घर आई हैं। बीते 17 अगस्त को उन्हें एक कॉल प्राप्त हुआ। जिसमें कहा गया कि उनका मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए नौ दबाने का विकल्प दिया गया। यह विकल्प चुना तो सामने से बोले व्यक्ति ने बताया कि उनकी आईडी पर एक दूसरा सिम कार्ड 15 जुलाई को मुंबई में सक्रिय किया गया है। वह नंबर अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। उसके साथ महिला की आईडी पर लिए गए सभी नंबर बंद किए जाने की बात कही। नर्स घबरा गई। आरोपी गैंग ने इसके बाद महिला को वीडियो कॉलिंग एप पर अपने साथ जोड़ लिया। सामने पुलिस कार्यालय जैसे माहौल दिखाया गया। वीडियो कॉल पर बात कर रहे व्यक्ति ने खुद का परिचय पुलिस अफसर प्रदीप सांवत के रूप में दिया। उसने नर्स को डराया कि उनका आधार कार्ड केनरा बैंक के एक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल है। मामला नरेश गोयल फ्राड से जुड़ा है। इसके बाद एक व्यक्ति को सीबीआई इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा बताते हुए बात कराई गई। आरोपी नर्स को डिजिटल गिरफ्तार बताते हुए मानसिक रूप से डराया कि उनके पास गिरफ्तारी के पूरे सबूत हैं। कोर्ट में सबूत ही माने जाते हैं। आरोपियों ने महिला को उनके बैंक खाते में जमा रकम क्लीयरेंस के लिए आरबीआई में फ्रीज कराने को कहा। इसके लिए पूणे का एक बैंक खाता नंबर भेजा गया। पीड़िता एसबीआई की हर्रावाला शाखा गई। वहां जाकर अपने बैंक खाते से आरोपियों के दिए बैंक खाते में 15.09 लाख रुपये जमा करवा दिए। इसके बाद भी आरोपी जांच का हवाला देते हुए नर्स को वीडियो कॉल पर बने रहने की बात कहते रहे। तब नर्स को आरोपियों के ठग होने का शक हुआ। इसके बाद पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में लिखित शिकायत दी। वहां से जीरो एफआईआर दर्ज कर केस को रायपुर थाने ट्रांसफर किया गया। रायपुर थाना पुलिस ने मामले में साइबर ठगी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संपादकीय

'जातिवाद' का अनर्गल अलाप

मिस इंडिया, बॉलीवुड, ओलंपिक खिलाड़ी एवं क्रिकेटर, उद्योगपति, मीडिया और न्यायपालिका आदि में आरक्षण लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों का सरकार और आरक्षण से क्या लेना-देना है? वे अधिकतर गैर-सरकारी क्षेत्र हैं। नौकरशाही और सरकारी न्यायपालिका में आरक्षण कुछ हद तक लागू होता है। 'मिस इंडिया' सौंदर्य, फैशन और बौद्धिकता के संगम का खुला मंच है। यदि दलित, आदिवासी, पिछड़े ऐसी प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहते हैं, तो एक दिन 'मिस इंडिया' ही नहीं, 'मिस वर्ल्ड' और 'मिस यूनिवर्स' के ताज भी पहन सकती हैं। रीता फारिया पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं, जिन्होंने 1966 में 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीता था। वह सवर्ण नहीं थीं, बल्कि घोर अल्पसंख्यक 'पारसी' समुदाय की थीं। इस समुदाय की आबादी आज भी एक लाख से कम है। किसी ने आज तक सवाल नहीं किया कि रीता ने ऐसी अभूतपूर्व और अंतरराष्ट्रीय सफलता कैसे अर्जित की? ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम में अक्सर सिख और जाट समुदाय के खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं। वे अल्पसंख्यक और ओबीसी हैं। ओडिशा के आदिवासी खिलाडियों ने भी ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेली है। दुनिया उनके बेमिसाल खेल को जानती है। उन्हें दलित, ओबीसी, आदिवासी के आधार पर टीम में शामिल नहीं किया गया। वे सक्षम, बेजोड़ खिलाड़ी रहे हैं, लिहाजा भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बॉलीवुड रचनात्मक चेहरों का विशाल और व्यापक समंदर है। रचनात्मक प्रतिभा बड़ी दुर्लभ होती है। किसी को आरक्षण के जरिए अभिनेता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, कैमरामैन आदि नहीं बनाया जा सकता। अलबत्ता लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रतिभाएं निखर भी उठती हैं। एनएसडी और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट इसके विरले उदाहरण हैं। बॉलीवुड के समंदर में दलित, पिछड़े, आदिवासी भी होंगे! राहुल गांधी कैसे दावा कर सकते हैं कि वहां इन जातियों के चेहरे नहीं हैं? मीडिया का हुनर और रचनात्मक कौशल भी भिन्न है। हर आदमी यह काम नहीं कर सकता। जोखिमों से खेलना पड़ता है और एक अच्छा लेखक भी बुनियादी कुशलता है। हम असंख्य दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जानते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय मीडिया में बुलंदियां छुई हैं। उनमें कुछ संपादक भी रहे हैं। उद्योगपति ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें औद्योगिक साम्राज्य विरासत में मिले हैं और उन्होंने अपने ज्ञान, मार्केटिंग, मेहनत, निवेश से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। कइयों ने निजी प्रयास से औद्योगिक कंपनियां स्थापित की हैं। उद्योग निजी क्षेत्र है, जिसमें आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षण नहीं है और न ही दिया जा सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी जो प्रगति कर चुके हैं और शहरों में अच्छी नौकरी करते हैं, वे शेयर बाजार में अच्छा-खासा निवेश करते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। राहुल गांधी की 'रिसर्च टीम' ने उन्हें ऐसे तथ्य नहीं बताए। सवाल है कि क्या किसी को आरक्षण के आधार पर उद्योगपति या किसान तक भी बनाया जा सकता है? कदापि नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आजकल 'जातीय जनगणना' का जुनून सवार है। वे सिर्फ 70 फीसदी या 90 फीसदी आबादी की भागीदारी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो करीब 55 साल देश पर शासन किया है। तब उसने 'जातीय भागीदारी' को सुनिश्चित क्यों नहीं किया? राहुल और अखिलेश से ही पूछ लिया जाए कि यदि देश में 'जातीय जनगणना' करवा ली जाए, तो आप उसे क्रियान्वित कैसे करेंगे? आजकल 'जातीय अनर्गल अलाप' करना खासकर उन दोनों की राजनीति है। यह सोच और नीति निजी क्षेत्र या निजी प्रतिभा, निजी निवेश और अनुसंधान पर लागू कैसे हो सकती है?

दैनिक न्यूज़ वायरस
संपादक : मौ.सलीम सैफी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मौ.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से प्रकाशित। **फ़ोन :** 0135-4066790, 2672002
RNI No. : UTTHIN/2012/44094 **Cert. Ser. No. :** 31406 **E-mail :** dainiknewsvirus@gmail.com
Website : www.newsvirusnetwork.com **YouTube :** TV News Virus
न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखंड), भारत

फिर रिलीज हो रही है इंडिया की ये नंबर 1 हॉरर फिल्म

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 28 अगस्त : 2018 में रिलीज हुई 'तुम्बाड' उन भारतीय फिल्मों में से है, जिसने ये साबित कर दिया की आज भी कंटेंट ही किंग है। तलवार से लेकर सिमरन जैसी फिल्मों में अलग-अलग रोल में नजर आए सोहम शाह जब दर्शकों के बीच तुम्बाड लेकर आए तो इसे देखने में जैसे दर्शकों के पसीने ही छूट गए। इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 8.2 रेटिंग मिली है। इन दिनों ये फिल्म एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, सोहम शाह की ये शानदार फिल्म 30 अगस्त को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 2018 में जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो दर्शकों के पसीने छूट गए थे। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया था और इसने कई नेशनल-इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते थे।

फिर सिनेमाघरों में रिलीज होगी तुम्बाडइन दिनों वैसे भी भारतीय दर्शकों के बीच हॉरर फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है। इस साल रिलीज हुईं दो हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर 'स्त्री 2' तो अब भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है। इससे पहले हॉरर-कॉमेडी 'मुंज्या' ने दर्शकों को खूब डराया और लोगों को डरा-डरा कर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन कर लिया। अब हॉरर फिल्मों के दीवानों के लिए सोहम शाह ने

अपनी नंबर 1 हॉरर फिल्म 'तुम्बाड' को फिर रिलीज करने का फैसला लिया है।तुम्बाड को बनने में लगे 7 सालेलेकिन, क्या आप जानते हैं इस फिल्म बनाने में निर्माता को पूरे 7 साल लगे थे। यही नहीं, फिल्म बनाने में सोहम शाह को अपने फ्लैट और प्रॉपर्टी से लेकर कार तक बेचनी पड़ गई थी। दरअसल, इस फिल्म को बनने में काफी समय लग रहा था, ऐसे में फिल्म से जुड़े एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े। सोहम शाह ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया था। यही नहीं, सोहम इस फिल्म को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद भी काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें बिलकुल उम्मीद नहीं थी कि फिल्म को इतना पसंद किया जाएगा।तुम्बाड की कहानीतुम्बाड की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी 1918 में महाराष्ट्र के एक तुम्बाड नाम के गांव से शुरू होती है, जहां विनायक (सोहम शाह) अपनी मां और भाई के साथ रह रहा होता है। यहां एक बाड़े में खजाने की बात होती है, जिसकी तलाश विनायक और उसकी मां को भी होती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि विनायक की मां उसे लेकर पुणे चली जाती है। 15 साल बाद जब विनायक गांव वापस आता है तो खजाने की तलाश में जुट जाता है, इसके बाद उसका सामना हस्तर से होता है, जिस पर श्राप है कि उसे उसके लालच और भूख की वजह से कभी नहीं पूजा जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए ये फिल्म आप या तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं या फिर 30 अगस्त को सिनेमाघरों में।

कांग्रेस जल्द शुरू करेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा : धस्माना

देहरादून। कांग्रेस जल्द केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को शुरू करने जा रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस स्थान पर यात्रा को स्थगित किया गया था, वहीं से यात्रा शुरू की जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थिति सामान्य होते ही कांग्रेस यात्रा शुरू करेगी। भाजपा ने श्रीकेदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को जिस तरह नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके लिए भाजपा को पूरे सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली बौराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर निर्माण का काम भाजपा की शह पर शुरू हुआ। केदारनाथ धाम से शिला दिल्ली ले जाने का पाप किया गया। श्रीकेदारनाथ धाम के नाम से बाकायदा ट्रस्ट बनाया गया। दुनिया भर से चंदा मांगा गया। इसे पैसे को बीकेटीसी के खाते में जमा कराया जाए। भाजपा के इस जघन्य पाप के खिलाफ प्रदेश भर से लोगों ने आवाज उठाई। आम लोगों की इसी आवाज को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू किया। हरिद्वार से इस यात्रा को श्री केदारनाथ धाम तक जाना था। यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। रुद्रप्रयाग से आगे पहुंचने पर आपदा से हुए नुकसान और केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के ध्वस्त होने पर यात्रा को रोका गया। कांग्रेसियों ने यात्रा रोक, आपदा राहत बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग किया। अब जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा।

कहा कि भाजपा को श्रीकेदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को लेकर किए गए कामों पर जवाब देना होगा। बताना होगा कि गर्भ गृह में जो 228 किलो सोना लगाने के जो दावे किए गए थे, वो अब सोने के पीतल बनने पर कहां गए। क्योंकि बीकेटीसी अध्यक्ष ने खुद 228 किलो सोने का दावा किया था। शंकराचार्य की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। बताना होगा कि गर्भ गृह में फोटोग्राफी करवा कर किसने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। क्यों कृष्णा माई गुफा का नाम बदला गया। बताना होगा कि कौन केदारनाथ धाम से शीला लेकर दिल्ली गया। इस अवसर पर प्रवक्ता गरिमा दसोनी, अमरजीत सिंह, शीशपाल बिष्ट आदि मौजूद रहे।

मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश, पर्वतीय ITI में इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक होंगे पाठ्यक्रम

टॉपर प्रशिक्षणार्थियों को बेस्ट आईटीआई / स्किल सेंटर में कराएँगे भ्रमण : सौरभ बहुगुणा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 28 अगस्त , उत्तराखंड के विकास और रोज़गार में वृद्धि के लिए नए नए प्रयोग , योजनाएं और नवाचार को बढ़ावा दे रहे कैबिनेट मंत्री कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों एवं देश की प्रतिष्ठित इंडस्ट्री टाटा टेक्नोलॉजी, फिलिप्स एवं श्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ राज्य की मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र के आईटीआई में भी इंडस्ट्री की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करने पर चर्चा की गई।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्री की मांग के अनुसार इंडस्ट्री के माध्यम से वर्तमान में श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से आईटीआई काशीपुर में होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल एवं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के तीन माह के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें इंडस्ट्री द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है इसी प्रकार आईटीआई रोशनाबाद हरिद्वार में भी प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन (मिलिंग) एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निशियन (टर्निंग) के तीन माह के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं दोनों सी ओ ई में प्रशिक्षित होकर 90% से अधिक युवा देश की प्रतिष्ठित इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं

इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि इन सी ओ ई में प्रशिक्षित युवा अधिक वेतन का रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन इंडस्ट्री में यह कार्य कर रहे हैं उन इंडस्ट्री से भी उनके कार्य एवं व्यवहार का अच्छा फीड बैंक प्राप्त हो रहा है। इन सी ओ ई की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा स्किल हब सहसपुर में फिलिप्स के सहयोग से प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग एवं श्नाइडर के सहयोग से एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी तथा फेस्टो के सहयोग से हाइड्रोलिक, न्यूमेंटिक, मेकाट्रॉनिक्स एवं रोबोटिक्स के सी ओ ई संचालित किए जाने हैं जो कि अंतिम चरण में है विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 13 आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे हेतु आवश्यक भवन बनाए जाने का प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित कर दिया गया है

इस पर दूरदर्शिता के साथ मंत्रालय को नई ऊंचाइयां दे रहे मंत्री बहुगुणा ने निर्देश दिए कि राज्य के मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र के आईटीआई में भी इस प्रकार के सी ओ ई का लाभ पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को भी दिए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए तथा इंडस्ट्री प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराएं तथा जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा है उन संस्थानों को हब के रूप में विकसित किया जाए तथा जहां छात्रावास की सुविधा नहीं है उनको स्पोक के रूप में विकसित किया जाए ताकि राज्य के अधिकांश आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षणन वीनतम मशीनों पर दिया जा सके तथा उन्हें रोजगार हेत इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके साथ ही मंत्री सौरभ ने कहा कि आईटीआई में इस वर्ष उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों में से टॉपर प्रशिक्षणार्थियों को देश केअच्छे आईटीआई अथवा स्किल सेंटर में भ्रमण पर भेजा जाए। चर्चा के दौरान सचिव कौशल विकास एवं संयोजन विजय कुमार यादव, फिलिप्स एजुकेशन से रक्षित केजरीवाल एवं स्नाइडर इलेक्ट्रिक से श्रीकांत राव एवं टाटा टेक्नोलॉजी से प्रशांत आदि मौजूद थे।

ज्योति पर बरसी लाठियां, भाजपा पर बरसी कांग्रेस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रपुर , 28 अगस्त , महिला अपराधों के खिलाफ रुद्रपुर की सड़कों पर महिला कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने में उत्तराखंड पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान मित्र पुलिस का व्यवहार बेहद आक्रामक और सख्त नज़र आया क्योंकि जिस तरह से एक महिला और प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला को हवा में उठा उठा कर फेंका गया वो सबके लिए चौंकाने वाला मंजर था। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेटिंग पर काफी सख्त प्रदर्शन करते हुए ज्योति रौतेला को हांथों में उठाये रखा। अब ये वीडियो पूरे प्रदेश में सियासी गर्माहट को बढ़ा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी मातृशक्ति को दिए गए ये जख्म हुक्मरानों के दम्भ की दास्तान कह रहे हैं। विधि अनुसार विरोध व्यक्त करना संवैधानिक अधिकार है । यह दृश्य स्पष्ट बताते हैं कि सरकार पुलिस का उपयोग जनता के रोष, क्रोध के दमन व अधिकारों के हनन हेतु कर रही है । प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या व घोर निंदनीय कृत्य है ।महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों, बलात्कारों के विरोध में महिला हितों की आवाज बुलंद करने रुद्रपुर में आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा महिलाओं पर बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाना, संवैधानिक अधिकार का हनन है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या व घोर निंदनीय कृत्य है और सरकार की दमनकारी मानसिकता को दर्शाता है।सब रहेगा याद, जनता लेगी हिसाब

आपको यहाँ बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस जब सड़कों पर अपना विरोध जताने रुद्रपुर पहुंची तो जो नज़ारा दिखा वो हैरान करने वाला था रुद्रपुर की सड़कों पर महिला उत्पीड़न के विरोध में ज्योति रौतेला और प्रदर्शनकारी महिलाएं उतरी तो पुलिस से उनका सामना हुआ और फिर जो हुआ वो आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पुलिसकर्मियों ने आंदोलन करने से रोकने के लिए जमकर ताक़त का इस्तेमाल किया।

देर शाम बयान जारी करते हुए घटना में घायल हुयी ज्योति रौतेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध और बलात्कार हत्या जैसी शर्मनाक घटनाएं होंगी तो क्या महिलाएं उसका विरोध भी नहीं कर सकती है ? उन्होंने पुलिस के दुर्व्यवहार पर दुःख जताते हुए कहा कि उनके साथ जो अभद्रता सरे बाज़ार हुयी है उसके ज़िम्मेदारों पर क्या कोई एक्शन होगा ? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कुशासन व जंगलराज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार एवं अपराध के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वैमनस्य सरकार की पुलिस द्वारा महिलाओं पर बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाना, संवैधानिक अधिकार का हनन है। ये निरंतर अलोकप्रिय होती जा रही भाजपा सरकार की बढ़ती हताशा का प्रतीक है।